

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार 15 नवम्बर से प्रदेश में चिट्ठे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरंभ करेगी और इसे समूल नष्ट किया जाएगा। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि चिट्ठे के खिलाफ आगामी 3 माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का शुभारम्भ 15 नवम्बर को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक एंटी चिट्ठा रैली से किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में चिट्ठा से सबसे अधिक प्रभावित पंचायतें चिन्हित कर ली गई हैं और इन पंचायतों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों और नशे के सेवन व अवैध कारोबार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर नशा निर्वारण समितियों का गठन किया जाएगा।

चंद्र कुमार

कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को कृषि अवसंरचना कोष के तहत किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वे आज पालमपुर में कृषि अवसंरचना कोष के तहत आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि अवसंरचना के तहत स्वीकृत होने वाली योजनाओं में किसानों को 6 फीसदी की दर से ऋण मिलता है जो उनकी आय व आजीविका सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण सात वर्ष तक के लिए 6 प्रतिशत ब्याज पर ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग संस्थानों के साथ तालमेल स्थापित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद भी किया।

जीएस.टी

जीएसटी बचत उत्सव से देशभर के लोगों को लाभ हो रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में सुधार के साथ इस उत्सव की शुरुआत की थी। इन सुधारों से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लोगों को काफी लाभ पहुंचा है। एक रिपोर्ट—

नई जीएसटी सुधारों ने कर के बोझ को काम करके और प्रमुख उपकरणों को अधिक किफायती बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। अब टेलीविजन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा, जिससे घरों, स्कूलों और कार्यालय की लागत कम हो जाएगी। इसी प्रकार एयर कंडीशनर और डिशवाशर पर कर की दर 28% से घटकर 18% कर दी गई है, जिससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स अधिक नागरिकों के लिए सुलभ हो गए हैं। वहीं सौर पैनल और कंपोस्टिंग मशीन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था अब 5% कर स्लैब में आ गए हैं। जिससे हरित विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए नई दिल्ली के एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर पंकज पांडे ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी में कमी से बिक्री में वृद्धि हुई है और अब उपभोक्ता इन वस्तुओं पर 3 से 4 हजार तक की बचत कर रहे हैं।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओं में जाईका वानिकी परियोजना द्वारा खोले गए मल्टीपर्पज आउटलेट का लोकार्पण किया। इसमें परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित सभी तरह के प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री होगी। इस अवसर पर जगत सिंह नेगी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ संवाद कर उनकी आर्थिकी के बारे में चर्चा की। उन्होंने वानिकी परियोजना द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान परियोजना निदेशक श्रेष्ठा

नंद शर्मा ने बताया कि जाइका वानिकी परियोजना प्रबंधन ने प्रदेश के 22 वन मंडल स्तर पर आउटलेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के कोटखाई स्थित मुख्यमंत्री आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये संस्थान क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित बड़ा संस्थान है जहां विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को रोगी कल्याण समिति द्वारा अर्जित धन राशि को संतुलित व विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिए।

एचपी शिवा

एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश के सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, सोलन और सिरमौर में वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित क्लस्टरों की स्थापना की गई है। परियोजना निदेशक देवेंद्र सिंह ठाकुर ने शिमला में दुबई के एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना किसानों को केवल उत्पादन तक समिति नहीं रख रही बल्कि उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर रही है।

साक्षरता शिविर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रणजीत सिंह ने कहा कि शिविर का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे जागरूक करना और आपदा पीड़ितों के पुनर्वास सहित अन्य जानकारी प्रदान करना है।
